Statement -III

(Rupees in crores)

S.No.	Scheme	*Allocation of Central Funds (Plan) for* 1995-96
1.	Special Projects for Eradication of Illiteracy	120.00
2.	Scheme of assistance to voluntary agencies	10.00
3.	Post Literacy and Continuing Education	66.00
4.	Strengthening of Administrative Structures	14.00
5.	Rural Functional Literacy Project	6.00
6.	Directorate of Adult Education	12.00
7.	Shramik Vidyapeeth	4.35
8.	Technology Demonstration	0.15
9.	Cultural Exchange Programme	0.25
10.	National Institute of Adult Education	0.50
11.	National Literacy Mission Authority	0.75
	TOTAL:	234.00

विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी विषय

2933. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक कृषि को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का है ;

(ख) क्या सरकार विद्यालयों में बागवानी और पशुपालन जैसे रोजगारोन्मुखी विषय भी आरम्भ करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या में कृषि का अनिवार्य विषय के रूप में प्रावधान नहीं है। तथापि पर्यावरण अध्ययन, कार्य अनुभव तथा जीव विज्ञान के जरिए कृषि को किसी न किसी रूप में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है।

(ख) से (घ) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश के चुने गए माध्यमिक विद्यालयों में कृषि से जुड़े अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बागवानी से जुड़े पाठ्यक्रम 14 राज्यों के लगभग 363 स्कूलों में तथा पशुपालन से जुड़े पाठ्यक्रम 10 राज्यों के 312 स्कूलों में शुरू किए गए हैं।